Loss due to inefficiency of the International Airport Authority of India

2044. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that inept functioning of International Airport Authority of India has caused huge losses to the cargo shippers and International Airlines; and

(b) if so, what steps Government propose to take to tone up the functioning of the International Airport Authority of India?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) There have been some problems in the nature of teething troubles when the New Cargo Terminal at Delhi Airport had started its operation. The Government however, do not have any specific details about any losses incurred by Cargo Shippers or international airlines on this account. The teething troubles have since been overcome and the Cargo Terminal is now functioning satisfactorily.

Blood donations to hospitals

2045 SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Television programmes on AIDS, which were repeatedly telecast from Bombay recently, had his Ministry's prior approval; and

(b) if not, whether in future Government would make it obligatory to get Health Ministry's prior approval before such programmes are telecast on television to avoid a similar scare which the programmes on AIDS have created resulting in fall in blood donations particularly in Bombay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) Yes.

(b) Does not arise. There has also been no indication so far about any steep decline in blood donation during the current year.

बाल सुरक्षा गृहों का स्थापित किया जाना

2046. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल अपराधियों को कारागारों की चार दीवारी से बाहर रखे जाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर बाल सुरक्षा गृहों की स्थापना किये जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को क्या निदेश जारी किये हैं;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने ऐसे गृह स्थापित करने के लिए पहल की है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार इसके लिये नए प्रस्ताव पेश करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने बाल अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत बाल अपराधियों की देखभाल, उपचार और पुनर्वास के लिए संस्थान स्थापित किये जाते हैं। भारत सरकार, बाल अधिनियमों के अन्तर्गत बाल गृहों की स्थापना करने की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों से आग्रह कर रही है, ताकि बच्चे आइंदा जेलों मे न रखे जाएं।

(ख) व्यावहारिक तौर पर सभी राज्यो सरकारो ने बाल अधिनियम बना लिये है और संस्थान स्थापित कर लिये हैं या करने वाले हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।